गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 111
दि. 21.08.2025,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

पीएम 22 अगस्त को बिहार और प. बंगाल का दौरा करेंगे

पीएम गया में लगभग 13,000 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे

परियोजनाएं बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शहरी विकास और जल आपूर्ति जैसे क्षेत्रों से संबंधित

पीएम गंगा नदी पर औंटा-सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच संपर्क बढ़ेगा

नए पुल से भारी वाहनों के लिए 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी कम होगी और सिमरिया धाम तक पहुंचना आसान होगा

पीएम गया और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस तथा वैशाली और कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे

(जीएनएस)।

पीएम श्री नरेन्द्र मोदी 22 अगस्त को बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। वह सुबह लगभग 11 बजे बिहार के गया में लगभग 13,000 करोड़ रुपये की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी दो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद, वे गंगा नदी पर औंटा-सिमरिया पुल परियोजना का दौरा करेंगे और उसका उद्घाटन करेंगे।

पीएम शाम लगभग 4:15 बजे कोलकाता में नवनिर्मित खंडों पर मेट्रो ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे और जेसोर रोड मेट्रो स्टेशन से जय हिंद बिमान बंदर तक मेट्रो की सवारी करेंगे और वापस आएंगे। इसके अतिरिक्त, वह कोलकाता में 5,200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे।

बिहार में पीएम कनेक्टिविटी में सुधार की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, पीएम राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर 8.15 किलोमीटर लंबी औंटा-सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिसमें गंगा नदी पर 1,870 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित 1.86 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल भी शामिल है। यह पटना के मोकामा और बेगूसराय के बीच सीधा संपर्क प्रदान करेगा।

यह पुल पुराने 2-लेन वाले जर्जर रेल-सह-सड़क पुल "राजेंद्र सेतु" के समानांतर बनाया गया है, जिसकी हालत खराब होने के कारण भारी वाहनों को अपना रास्ता बदलना पड़ता है। यह नया पुल उत्तर बिहार (बेगूसराय, सुपौल, मधुबनी, पूर्णिया, अररिया आदि) और दक्षिण बिहार के क्षेत्रों (शेखपुरा, नवादा, लखीसराय आदि) के बीच आवागमन करने वाले भारी वाहनों के लिए 100 किलोमीटर से अधिक की अतिरिक्त दूरी की यात्रा को कम करेगा। इससे क्षेत्र के अन्य हिस्सों में वाहनों को रास्ता बदलने के कारण लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या को भी कम करने में मदद मिलेगी।

इससे आसपास के क्षेत्रों, विशेषकर उत्तर बिहार, में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, जो आवश्यक कच्चे माल की प्राप्ति के लिए दक्षिण बिहार और झारखंड पर निर्भर हैं।

पेट्रोल कारों से इलेक्ट्रिक कारों तक: गुजरात बन रहा भारत का ऑटोमोटिव हब

भारत की ऑटो क्रांति का केंद्र उत्तर गुजरात, VGRC के लिए तैयार

गांधीनगर, 20 अगस्त : 7.5 लाख कार यूनिट प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता वाले सुजुकी मोटर्स के गुजरात प्लांट के साथ, उत्तर गुजरात भारत के प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माण केंद्रों में से एक बन चुका है। ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए यहाँ मौजूद मजबूत व अनुकूल बुनियादी ढांचा, निवेश-अनुकूल नीतियां और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति ने इस क्षेत्र को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए आकर्षक केंद्र बना दिया है।

इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सुजुकी मोटर्स ने ₹3,200 करोड़ का निवेश करके अपनी चौथी प्रोडक्शन लाइन स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। इससे न केवल उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि गुजरात में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति भी सुनिश्चित होगी।

2012 से 2015 के बीच गुजरात में अंतरराष्ट्रीय ऑटोमोबाइल कंपनियों के निवेश की एक लहर देखने को मिली। 2014 में सुजुकी द्वारा राज्य में मेगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए टङ्कव पर हस्ताक्षर करना इस निवेश यात्रा का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। गुजरात उनके इस भरोसे पर पूरी तरह से खरा उतरा और इसके बाद से कंपनी ने राज्य में लगातार निवेश किया, जिससे रोजगार के व्यापक अवसर उत्पन्न हुए। आज, सुजुकी मोटर्स का गुजरात प्लांट भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्माण प्रतिष्ठानों में शामिल है और इसने मेहसाणा क्षेत्र में ऑटो कम्पोनेंट उद्योग में बड़े पैमाने पर निवेश को भी गति दी है।

इसके अलावा, गुजरात की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति और यहाँ मौजूद मजबूत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी राज्य को वैश्विक ऑटोमोबाइल निर्यात के लिए एक रणनीतिक केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया है। 2024 में राज्य ने लगभग ₹3,459 करोड़ के ऑटो निर्यात में योगदान दिया है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, जापान, वअए और चिली प्रमुख निर्यात गंतव्य रहे।

साथ ही, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में गुजरात में वित्त वर्ष 2022झ23 में निवेश ₹29,700 करोड़ तक पहुंचा, जो पिछले पांच वर्षों में 16.4% की मजबूत उअऋक्ष का संकेत देता है। राज्य का मांडलझबेचराजी स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (रक्फ़) अब प्रमुख ऑटो-औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरा है।

हाल ही में सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने दो प्रमुख घोषणाएं भी की हैं:

- इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी प्लांट (₹7,300 करोड़) की स्थापना
- ईवी निर्माण सुविधा (₹3,100 करोड़) की स्थापना

गुजरात को वैश्विक विनिर्माण हब बनाने के संकल्प के साथ राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों और आकर्षक प्रोत्साहनों ने अंतरराष्ट्रीय ऑटोमोबाइल कंपनियों का भरोसा लगातार मजबूत किया है। और इसी दिशा में ये पहलें न केवल गुजरात की औद्योगिक क्षमता को नई ऊर्जा देती हैं, बल्कि स्पष्ट रूप से इसे एक वैश्विक ऑटोमोबाइल पावरहाउस के रूप में स्थापित करने की दिशा में अग्रसर करती हैं।

भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ ने एफटीए पर वार्ता शुरू करने के लिए संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए

(जीएनएस)।

भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ (ईएईयू) ने आज मॉस्को में मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत शुरू करने के लिए संदर्भ शर्तों (टीओआर) पर हस्ताक्षर किए। इसमें आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य और रूसी संघ शामिल हैं। भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के अपर सचिव श्री अजय भादू और यूरेशियन आर्थिक आयोग (ईईसी) के व्यापार नीति विभाग के उप निदेशक श्री मिखाइल चेरेकाएव ने इस संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए।

अपनी यात्रा के दौरान, भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के अपर सचिव श्री अजय भादू ने ईईसी के व्यापार प्रभारी मंत्री श्री आंद्रेई स्लेपनेव से भी मुलाकात की। वार्ता समूहों के प्रमुखों ने मंत्री महोदय को संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर के साथ प्राप्त हुई उपलब्धि से अवगत कराया और भावी व्यापार समझौते के संगठनात्मक पहलुओं सहित वार्ता प्रक्रिया को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए अगले कदमों पर चर्चा की।

दोनों पक्षों ने भारत और ईएईयू के बीच बढ़ते व्यापार के कारोबार पर ध्यान दिया, जो 2024 में 69 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और 2023 की तुलना में 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। 6.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद के साथ, प्रस्तावित एफटीए से भारतीय निर्यातकों के लिए बाजार पहुंच का विस्तार होने, नए क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में विविधीकरण का समर्थन करने, गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है।

परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा का पुनर्मूल्यांकन

दुनिया में कहीं भी परमाणु सुरक्षा से संबंधित किसी भी बड़ी घटना के बाद सुरक्षा का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है ताकि सुरक्षा सुविधाओं को और मजबूत करने की आवश्यकता की जांच की जा सके। जापान में रिक्टर पैमाने पर 9.0 की तीव्रता वाले भूकंप और उसके बाद वर्ष 2011 में फुकुशिमा दाइची परमाणु दुर्घटना के बाद भारतीय एनपीपी के लिए एईआरबी द्वारा स्वतंत्र रूप से ऐसे पुनर्मूल्यांकन किए गए थे ताकि भूकंप, बाढ़ और उनके संभावित प्रभावों जैसी गंभीर प्राकृतिक घटनाओं से निपटने के लिए क्षमताओं और मार्जिन का निर्धारण किया जा सके। उपरोक्त सुरक्षा आकलन और किए गए सुरक्षा उपाय हाल ही में रूस और जापान में आए 8.6 रिक्टर पैमाने के भूकंप पर भी लागू होते हैं।

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ में बाल स्वास्थ्य पर 30वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन

आयुर्वेद की बाल-देखभाल प्रणाली कौमारभृत्य से स्वस्थ बालक, स्वस्थ भारत का निर्माण हो सकता है: केंद्रीय मंत्री श्री प्रतापराव जाधव

संगोष्ठी में निवारक, प्रोत्साहनकारी और समग्र बाल स्वास्थ्य देखभाल में आयुर्वेद की भूमिका पर बल दिया गया

विशेषज्ञों ने भावी पीढ़ियों के निर्माण के लिए आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के साथ कौमारभृत्य प्रणाली को समायोजित करने का आ'ान किया

(जीएनएस)।

आयुष मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (आरएवी) ने आज नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित स्कोप कॉम्प्लेक्स ऑडिटोरियम में 'आयुर्वेद के माध्यम से बाल चिकित्सा में रोग एवं कल्याण प्रबंधन' विषय पर अपने 30वें राष्ट्रीय सेमिनार का सफलतापूर्वक समापन किया।

18-19 अगस्त 2025 तक आयोजित इस दो दिवसीय संगोष्ठी में देश भर के प्रख्यात आयुर्वेद विद्वानों, शोधकताओं, चिकित्सकों और छात्रों सहित 500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। संगोष ठी के दौरान हुए विचार-विमर्श में बच्चों में रोग प्रबंधन और स्वास्थ्य संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया गया, जिससे बाल स्वास्थ्य के प्रति आयुर्वेद के समग्र दृष्टिकोण की पुष्टि हुई।

केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने एक लिखित संदेश के माध्यम से अपने समापन संबोधन में कहा कि इस संगोष्ठी के परिणाम भारत के बाल चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा ढांचे को सुदृढ़ करेंगे। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद की कौमारभृत्य शाखा में निवारक, प्रोत्साहनात्मक और उपचारात्मक दृष्टिकोणों के समन्वय के साथ बाल स्वास्थ्य सेवा में परिवर्तन लाने की क्षमता है। पिछले दो दिनों में साझा किया गया सामूहिक ज्ञान, स्वस्थ बालक, स्वस्थ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नए शोध सहयोगों और व्यावहारिक मॉडलों को प्रेरित करेगा।

आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि इस संगोष्ठी ने बाल चिकित्सा आयुर्वेद में शैक्षिक आदान-प्रदान के लिए एक मानक स्थापित किया है। उन्होंने साक्ष्य-आधारित सत्यापन के महत्व पर बल देते हुए आयुर्वेदिक सिद्धांतों को आधुनिक स्वास्थ्य सेवा पद्धतियों के साथ समायोजित करने के लिए सहयोगात्मक अध्ययनों की आवश्यकता दर्शाई।

वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा ने योग और आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए बाल चिकित्सा कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आरएवी और एआईआईए की भी प्रशंसा की।

आरएवी की निदेशक डॉ. वंदना सिरोहा ने अपने समापन संबोधन में कहा कि संगोष्ठी की सफलता आयुर्वेद चिकित्सकों और शोधकताओं की अगली पीढ़ी को पोषित करने के लिए आरएवी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि शोधपत्र और पोस्टर प्रस्तुतियों में युवा विद्वानों की सक्रिय भागीदारी ने बाल चिकित्सा आयुर्वेद के उज्ज्वल भविष्य को प्रदर्शित किया है।

इस दो दिवसीय कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल थे:

आयुर्वेद में बाल स्वास्थ्य पर 20 वैज्ञानिक शोध पत्र प्रस्तुतियां

युवा विद्वानों द्वारा नवीन अध्ययनों को प्रदर्शित करने वाले पोस्टर सत्र

बच्चों में निवारक और प्रोत्साहनकारी स्वास्थ्य सेवा पर पैनल चर्चा

स्मारिका का विमोचन और सेमिनार किट एवं भागीदारी प्रमाणपत्र का वितरण

संगोष्ठी का समापन इस आम सहमति के साथ हुआ कि आयुर्वेद की समग्र बाल चिकित्सा पद्धतियों विशेष रूप से जीवनशैली संबंधी विकारों, पोषण संबंधी कमियों और बच्चों में उभरती स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान के लिए इन हें भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के पूरक के रूप में मुख्यधारा में लाया जाना चाहिए।

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने 'पशुधन उत्पादकता बढ़ाने हेतु आयोजित वर्चुअल जागरूकता कार्यक्रम' की अध्यक्षता की

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने आज 'पशुधन उत्पादकता बढ़ाने हेतु वर्चुअल जागरूकता कार्यक्रम' का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में देशभर के 2000 कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) से 1 लाख से अधिक पशुपालक किसान जुड़े। इनमें छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश शामिल रहे।

नकली कीटनाशक के संबंध में कृषि मंत्री को मिली शिकायतों पर कार्रवाई

बाजार से खरपतवार नाशक के सैम्पल जब्त कर की गई जांच, हर्बिसाइड के नमूने घटिया पाए गए

मध्य प्रदेश के 3 जिलों विदिशा, देवास व धार में डिफॉल्टर कंपनी के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर

जिन क्षेत्रों में खराब हर्बिसाइड बेचा गया, श्री शिवराज सिंह के निर्देश पर वहां डीलरों के लाइसेंस निलंबित

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह के निर्देश पर कंपनी के बचे हुए स्टॉक की बिक्री पर भी लगाई गई रोक

क्लोरिम्यूरॉन एथिल नामक हर्बिसाइड खरपतवार नाशक के प्रयोग से खराब हुई थी सोयाबीन की फसल

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने देशभर में व्यापक आकस्मिक छापामारी का अभियान चलाने के दिए निर्देश

(जीएनएस)।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश के कई किसानों से शिकायतें मिली थी कि क्लोरिम्यूरॉन एथिल 25% हढ नामक खरपतवार नाशक के प्रयोग से किसानों की सोयाबीन फसलें खराब हो रही हैं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने तुरंत कंपनी एवं डीलर्स पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद सैम्पल जब्त कर जांच की गई और नमूने घटिया पाए जाने पर मध्य प्रदेश के 3 जिलों विदिशा, देवास व धार में डिफॉल्टर कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ ही बचे हुए स्टॉक की बिक्री पर रोक लगाई गई है और डीलरों के लाइसेंस भी निलंबित कर दिए गए हैं। श्री शिवराज सिंह ने देशभर में व्यापक आकस्मिक छापामारी का अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद कृषि विभाग ने बाजार से उक्त हर्बिसाइड के सैंपल जब्त कर जांच कराई थी। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि संबंधित हर्बिसाइड घटिया गुणवत्ता का है और यही फसल के नुकसान का कारण बना है। इस संबंध में डिफॉल्टर कंपनी के खिलाफ विदिशा (ग्रामीण), देवास (कन्नौद), धार (बदनावर) जिले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4जी ब्रॉडबैंड

जून 2025 तक, पूर्वोत्तर क्षेत्र के 45,934 गाँवों में से (भारत के महापंजीयक के आँकड़ों के अनुसार), 42,093 गाँव मोबाइल कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं और इनमें से 40,663 गाँवों में 4ऋमोबाइल कनेक्टिविटी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में राज्यवार मोबाइल कवरेज की स्थिति अनुलग्नक में दी गई है।

किसी भी अछूते बसे हुए गाँव में मोबाइल कवरेज तकनीकी-व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा प्रदान की जाती है। सरकार, डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) के वित्तपोषण के माध्यम से, पूर्वोत्तर सहित देश के ग्रामीण, दूरस्थ और सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की स्थापना के माध्यम से दूरसंचार कनेक्टिविटी के विस्तार हेतु विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है।

सहकारी बैंकों के साथ पैक्स का एकीकरण

(जीएनएस)।

पैक्स कम्प्यूटरीकरण परियोजना के अंतर्गत सभी कार्यरत पैक्स को एक ईआरपी (उद्यम संसाधन नियोजन) आधारित साझा राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाया जा रहा है, जो उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ता है। यह साझा ईआरपी सॉफ्टवेयर परियोजना देशभर के सभी पैक्स को प्रदान किया गया है, ताकि पैक्स की सभी प्रकार की कार्यात्मक, ऋण और गैर-ऋण पर डेटा एकत्र किया जा सके। ईआरपी-आधारित साझा राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर एक साझा लेखा प्रणाली (सीएएस) और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के माध्यम से पैक्स संचालन की दक्षता को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त यह शासन और पारदर्शिता को मजबूत करता है जिसके परिणामस्वरूप ऋण वितरण में तेजी आती है। इससे लेनदेन लागत कम होती है, भुगतान असंतुलन

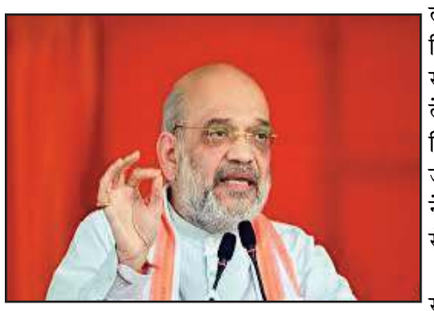

न्यूनतम होता है और डीसीसीबी और एसटीसीबी के साथ लेखांकन बेरोक-टोक होता है।

सहकारी बैंकिंग प्रणालियों के बीच डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और अंतर-संचालन को बढ़ाने के लिए शहरी सहकारी बैंकों के लिए राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम (एनयूसीएफडीसी) नामक संगठन की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य सामूहिक शक्तियों का लाभ उठाकर सहकारी बैंकों के डिजिटलीकरण में तेजी लाना, सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना तथा यह सुनिश्चित करना है कि सदस्य बैंक डिजिटल युग की जटिलताओं को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं।

इसके अलावा ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) को तकनीकी सेवाएं प्रदान करने और उनके सुदृढ़ीकरण के लिए आरबीआई ने सहकार सारथी (साझा सेवा इकाई) की स्थापना के लिए नाबार्ड को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है ।

सम्पादकीय

भारत-चीन अपने बीच के मुद्दे सुलझाने को प्रयासरत

मंगलवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी की विदेश मंत्री जयशंकर एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के साथ हुईं बैठकों को सार्वजनिक भले ही नहीं किया गया किन्तु जानकारी के मुताबिक आशा के अनुरूप दोनों ही बैठक सफल रहीं। विदेश मंत्री जयशंकर के साथ बैठक के दौरान चीनी विदेश मंत्री यी ने भारत की तीन प्रमुख चिन्ताओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। पहला भारत को उर्वरकों, दूसरा मृदा खनिजों, उच्चस्तरीय तकनीकी उत्पादों, जैसे इलेक्ट्रानिक वाहन, ड्रोन और बैटरी स्टोरेज के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। चीन वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रंखला में एक प्रमुख आपूर्ति कर्ता रहा है और तीसरी चिन्ता सुरंग खोदने वाली मशीनों की जरूरतों को चीन पूरा करेगा। दरअसल वैश्विक मृदा खनन में चीन का लगभग 70 प्रतिशत योगदान है। चीन 2023 तक भारत को भारी मात्रा में उर्वरक आपूर्ति करता था। किन्तु उसने भारत सहित कईं देशों का उर्वरक निर्यात रोक दिया था। इसी तरह उसने भारत से खनिज खोदने वाली मशीनों का निर्यात भी बंद कर दिया था। सच तो यह है कि भारत और चीन के बीच मित्रता तो है नहीं। दोनों देशों के बीच स्पष्ट और रचनात्मक संबंधों का अभाव तो रहा ही है, साथ ही लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के पास सीमावता क्षेत्रों में तनाव घटाने की प्रव्रिया भी 2020 से बिल्वुल स्थगित हो चुकी थी। दोनों देशों की सेनाओं के बीच चार साल तक गतिरोध बना रहा किन्तु अब सीमावार्ता में तेजी आने और दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली को प्रमुखता देने से लगता है कि दोनों देशों में उत्सुकता तो दिख ही रही है। असल में भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार की जरूरत दोनों को है। संबंधों के बीच कईं उतार-चढ़ाव आए किन्तु भारत और चीन ने अपने आयात-निर्यात पर बहुत ज्यादा ब्रेक नहीं लगाया था। भारत ने ही चीन के तमाम गैर जरूरी उत्पादों के आयात पर रोक लगाईं जबकि चीन ने भारत के उत्पादों के आयात पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगाया। 2020 में गलवान में हुए सैन्य टकराव के बाद चीन से भारत ने कच्चे माल ज्यादा आयात शुरू कर दिया। इसलिए आयात की मात्रा कम नहीं हुईं लेकिन चीन ने 2023 में उर्वरक, दुर्लभ मृदा खनिजों और सुरंग खोदने की मशीनें देना बंद कर दी तब भारत के लिए असहज स्थिति उत्पन्न हो गईं। कदाचित भारत इन तीनों ही वस्तुओं की आपूर्ति किसी और देश से करवाने का प्रयास कर सकता था किन्तु राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह भारत के खिलाफ टैरिफ के हथियार का इस्तेमाल किया उससे भारत ने खुद को ब्रिक्स और रिक यानि रूस, भारत व चीन की तिकड़ी के साथ खड़ा होना वूटनीतिक मजबूरी माना। विदेश मंत्री यी की विदेश मंत्री जयशंकर के बीच हुईं वार्ता के बाद चीन ने जिस तरह भारत की जरूरतों को महसूस किया है, इससे एक बात तो स्पष्ट हो गईं है कि भारत अब आंख मूंद कर अमेरिका के साथ नहीं रहेगा। भारत मानता है कि हमारी समझदारी इसी में है कि हम किसी पर पूरी तरह निर्भर न रहते हुए सभी देशों से संबंध बनाएं और निभाएं। किसी के साथ संबंधों की कीमत पर उसकी दुश्मनी के सहयोगी न बनें। अमेरिका भले ही लोकतांत्रिक देश है किन्तु वह कईं दशकों तक भारत के भरोसे और विश्वास से वंचित रहा है। बड़ी मुश्किल से पूर्व राष्ट्रपति बिल ाक्लटन के कार्यकाल में अपनी तमाम परम्परागत नीतियों को छोड़कर भारत के भरोसे और विश्वास को हासिल करने के लिए अमेरिका ने प्रयास किया। उसे बहुत हद तक सफलता भी मिली थी किन्तु ट्रंप ने एक ही झटके में भारत को एक बार फिर अपने से दूर करने पर विवश कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री यी की मंगलवा को हुईं मुलाकात और प्रधानमंत्री की एससीओ बैठक में शामिल होना तथा राष्ट्रपति शी जिन पिग से मिलने की योजना और मंगलवार को ही विदेश मंत्री जयशंकर द्वारा रूस की तीन दिवसीय यात्रा यानि भारत की रिक संबंधों को लेकर धुआंधार सव्रिय वूटनीति का सटीक संदेश यह है कि भारत अमेरिका से उतनी ही मित्रता रखेगा, जितनी कि नईं दिल्ली को जरूरत है मतलब यह कि भारत अब अमेरिका की समस्याओं की गठरी ढोने वाला नहीं है। यही नहीं अमेरिका को स्पष्ट संदेश है कि भारत अब रूस और चीन से अपने संबंधों को लेकर किसी तरह संकोच करने वाला नहीं है।

भारतीय डाक प्रणाली का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण

सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 अनुप्रयोगों, बुद्धिमान प्लेटफार्मों और परस्पर जुड़े इकोसिस्- टम को जोड़ती है

डीओपी आईटी 2.0 परियोजना के अंतर्गत, विभाग ने आधुनिक डाक प्रौद्योगिकी (एपीटी) नामक नए आंतरिक रूप से विकसित डाक और लॉजिस्टिक समाधान का कार्यान्वयन पूरा कर लिया है

(जीएनएस)।

डाक विभाग ने आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2012 (डीओपी आईटी 1.0) को लागू किया, जो एक मिशन मोड ई-गवर्नेंस परियोजना है, जिसका उद्देश्य विभाग को ग्राहकों के लिए बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित करते हुए एक प्रौद्योगिकी संचालित संगठन में बदलना है।

डीओपी आईटी 1.0 परियोजना की प्रगति और चुनौतियों के आकलन के लिए, परियोजना की मध्यावधि समीक्षा 2018 में आईआईएम, लखनऊ द्वारा की गई थी और परियोजना का अंतिम मूल्यांकन 2021 में एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष मूल्यांकनकर्ता, आईआईपीए (भारतीय लोक प्रशासन संस्थान) द्वारा किया गया था। अंतिम मूल्यांकन के कुछ प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं –

आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2012 के कार्यान्वयन के बाद विभाग ने 6.33 प्रतिशत की आंतरिक प्रतिफल दर (आईआरआर) हासिल की।

डाक विभाग की 'आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2012' द्वारा किए गए गुणात्मक और मात्रात्मक योगदान प्रभावी पाए गए हैं। गुणात्मक रूप से, सेवाओं की तीव्र डिलीवरी को प्रमुख सुधारों में से एक माना गया है। मात्रात्मक रूप से, सुलभ डाक सेवाओं की संख्या, विशेष रूप से बैंकिंग सेवाओं से वंचित/अल्प-बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए, बढ़ी है।

डाक परिचालन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कुशलतापूर्वक कार्य करता पाया गया है।

सर्वेक्षणों के अनुसार, डाक विभाग (डीओपी) के ग्राहक डाक कर्मचारियों से कुल मिलाकर संतुष्ट पाए गए। नेटवर्क कनेक्टिविटी के कारण आई तकनीकी खराबी से कुछ ग्राहक निराश हुए।

डीओपी आईटी 1.0 के क्रम में, सरकार ने 2022-23 से शुरू होने वाली आठ वर्षों की अवधि के लिए 5785 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 (डीओपी आईटी 2.0) को मंजूरी दी है।

सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 अनुप्रयोगों, बुद्धिमान प्लेटफार्मों और आपस में जुड़े इकोसिस्- टम को जोड़ती है ताकि विभिन्न वितरण चैनलों के माध्यम से अपने हितधारकों को डाक और वित्तीय सेवाओं का एक समावेशी, एकीकृत और एकल-खिड़की दृश्य प्रदान किया जा सके।

डीओपी आईटी 2.0 परियोजना के अंतर्गत, विभाग ने देश के सभी 1.64 लाख डाकघरों में आधुनिक डाक प्रौद्योगिकी (एपीटी) नामक नए आंतरिक रूप से विकसित डाक और लाजिस्टिक समाधान की शुरूआत पूरी कर ली है। यह डाक सेवाओं को तेज, सुरक्षित और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाएगा और डाकघरों को क्यूआर कोड आधारित डिजिटल भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाएगा।

डाक विभाग ने ग्रामीण जनता तक डाक, वित्त, बीमा और सरकारी सेवाएँ पहुँचाने के लिए देश के सभी ग्रामीण शाखा डाकघरों को एंड्रॉइड आधारित मोबाइल फोन उपलब्ध कराए हैं। एपीटी के अंतर्गत आंतरिक रूप से विकसित आंतरिक मोबाइल ऐप (आईएमए) अब इन फोनों में उपलब्ध है, जिसमें प्राप्तकर्ता के डिजिटल हस्ताक्षर लेना, वस्तुओं की डिलीवरी के लिए रीयल-टाइम अपडेट और एकीकृत डिजिटल भुगतान सुविधा (डायनेमिक क्यूआर कोड कार्यक्षमता का उपयोग करके) की क्षमता है।

इसके अलावा, कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस), भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी), डाक और पार्सल सेवाओं के क्षेत्र में पूरे देश में, दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों सहित, विभाग द्वारा की गई पहलों की सूची, वितरण अंतराल को कम करने, बुनियादी ढांचे की चुनौतियों का समाधान करने और भारतीय डाक प्रणाली के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण को आगे बढ़ाने के लिए अनुबंध-क के रूप में संलग्न है।

अनुबंध-I

कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) में पहल

ऑटोमेटिक टैलर मशीन (एटीएम) सुविधाएं

इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग।

डाकघर से बैंक और इसके विपरीत धन हस्तांतरण के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण (एनईएफटी) / रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) सेवाएं।

इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा (ईसीएस) सुविधा – बैंक खातों में ब्याज और परिपक्वता राशि जमा करने के लिए

शेष राशि और मिनी स्टेटमेंट देखने के लिए ई-पासबुक सुविधा।

सभी प्रकार के डिजिटल लेनदेन के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक-डाकघर बचत खाता लिंकेज सेवाएं।

इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस) सुविधा।

भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) में पहल

रीयल-टाइम डेटा साझाकरण

(जीएनएस)।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस), राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) जैसे विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों और राज्य सरकारों के बीच डेटा साझा करने के लिए रीयल-टाइम संचार चैनल मौजूद हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि आईएमडी और एनसीएस-एमओईएस क्रमशः इसरो, एनडीएमए और राज्यों के साथ चौबीसों घंटो के आधार पर रीयल-टाइम मौसम संबंधी और भूकंप संबंधी डेटा साझा करते हैं। आईएमडी द्वारा आपदाओं से संबंधित जानकारी, इसमें अवलोकन, पूर्वानुमान और चेतावनियाँ शामिल हैं, जिला स्तर तक एपीआई, सीएपी, ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप और सीधे प्रसारित की जाती है। आईएनसीओआईएस समुद्री घटनाओं जैसे सुनामी और उससे जुड़ी तूफानी लहरों, ऊँची लहरों आदि के लिए बहु-खतरे वाली प्रारंभिक चेतावनियाँ प्रदान करता है। आईएनसीओआईएस, आईएमडी के साथ समन्वय में, चक्रवातों के दौरान आँकड़ों का आदान-प्रदान और संयुक्त बुलेटिन भी जारी करता है। चेतावनियाँ एनडीएमए और राज्य सरकारों के साथ कई माध्यमों, मौसम और समुद्र ऐप के माध्यम से साझा की जाती हैं, जिनमें एनडीएमए का सीएपी-आधारित सचेत सिस्टम भी शामिल है। एनसीएस चौबीसों घंटे राष्ट्रीय भूकंपीय नेटवर्क का संचालन करता है, भूकंपों का पता लगाता है और भूकंप के मापदंडों का अनुमान लगाता है और एकीकृत प्रसार प्रणाली (यूडीएस) का उपयोग करके आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के साथ मापदंडों को साझा करता है। इसमें भूकम्प ऐप के माध्यम से विभिन्न हितधारकों के साथ वास्तविक समय में साझा करना भी शामिल है।

एनडीएमए और बीआईएस ने अपर्याप्त इमारतों और संरचनाओं के भूकंपीय रेट्रोफिटिंग के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। भूकंप जोखिम न्यूनीकरण में क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण सुविधाओं जैसे जीवन रक्षक भवनों के सुरक्षा ऑडिट और रेट्रोफिटिंग पर बल देता है। हालाँकि दिशानिर्देश और बजट आवंटन मौजूद हैं, लेकिन कार्यान्वयन की गति सीमित वित्तीय संसाधनों, तकनीकी विशेषज्ञता में कमी, कुछ स्तरों पर कम प्राथमिकता और अपर्याप्त सार्वजनिक एवं संस्थागत जागरूकता जैसे कारकों से बाधित रही है। हालाँकि इन चुनौतियों का समाधान करने के प्रयास जारी हैं और बेहतर क्षमता निर्माण, बेहतर समन्वय और इस मुद्दे पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने से स्थिति में सुधार की उम्मीद है।

आईएनसीओआईएस समुद्री जानकारी और बहु-खतरे की पूर्व चेतावनी सेवाएँ प्रदान करता है। इसमें सुनामी, तूफानी लहरें, ऊँची लहरें, उफान और चरम समुद्री परिस्थितियों में तेज समुद्री धाराओं के लिए अलर्ट और एसएमएस, सोशल मीडिया, ईमेल, वेबसाइट, सचेत प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और मोबाइल एप्लिकेशन आदि सहित कई संचार माध्यमों के माध्यम से हितधारकों को सलाहकार सेवाएँ प्रदान करता है।

समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिशानिर्देश (डीआरआर-2016 पर प्रधानमंत्री का 10 सूत्री एजेंडा) देश में भूभौतिकीय और जल-मौसम विज्ञान और क्रायोस्फेरिक (जीएलओएफ) आपदा घटनाओं के लिए आपदा-संबंधी तैयारियों हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम के रूप में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को तकनीकी और वैज्ञानिक फीडबैक के लिए आईएमडी, एनसीएस, आईएनसीओआईएस, एनसीसीआर, एनसीपीओआर और इसरो को शामिल करके खतरा मानचित्रण, नियमित अभ्यास और जागरूकता अभियानों के माध्यम से नियमित सार्वजनिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। एनडीएमए सभी आयु वर्गों को शामिल करते हुए देशव्यापी अभ्यास आयोजित करता है। इसके पूरक के रूप में जमीनी स्तर के समुदायों तक पहुंचने के लिए टीवी और रेडियो पर शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भूकंप, सुनामी और मौसम संबंधी चेतावनियों सहित आपदा संबंधी जानकारी संस्थागत वेबसाइटों, मोबाइल ऐप, एसएमएस अलर्ट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से प्रसारित की जाती है।

एनसीएस और आईएनसीओआईएस, एनडीएमए, स्कूलों, एसडीएमए और एनआईडीएम के साथ-साथ तटीय राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसियों के साथ समन्वय में कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और वार्षिक मॉक ड्रिल के माध्यम से भूकंप और सुनामी की तैयारियों को मजबूत करते हैं ताकि पहले प्रतिक्रियाकर्ता या जमीनी स्तर तक पहुँच बनाई जा सके। यह भारत में यूनेस्को-आईओसी "सुनामी तैयारी" कार्यक्रम का भी नेतृत्व करता है, जिसके तहत ओडिशा के 26 तटीय गाँवों को मान्यता मिली है, जो तटीय लचीलापन बनाने में महत्वपूर्ण है।

आईएनसीओआईएस को यूनेस्को-आईओसी के सुनामी चेतावनी नेटवर्क द्वारा सुनामी सेवा प्रदाता के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में सेवा प्रदान करता है और समुद्री खतरों की चेतावनी और क्षमता निर्माण के लिए अन्य देशों के साथ सहयोग करता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय-एनओएए साझेदारी के माध्यम से, भारत समुद्र विज्ञान संबंधी डेटा साझाकरण और संयुक्त अनुसंधान में संलग्न है, जबकि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय वैश्विक भूकंपीय डेटा सहयोग को भी मजबूत करता है। एनसीएस डेटा साझा करने के लिए वैश्विक भूकंपीय नेटवर्क, अंतर्राष्ट्रीय भूकंपीय आयोग (आईएससी), रूस और जापान और ताइवान की अन्य एजेंसियों और आईएनसीओआईएस के साथ काम करता है।

लद्दाख में अंतरिक्ष परियोजनाएं

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन देश में सुदूर संवेदन प्रेक्षणों में सुधार लाने के लिए 2027-2028 तक रिसोर्ससैट-3 व 3ए, रिसोर्ससैट-3एस और 3एसए, एचआरएसएटी, जी20 उपग्रह तथा तृष्णा उपग्रह का निर्माण कर रहा है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को भी लाभ होगा। कक्षा में स्थित भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रहों (काटोर्सैट-2 श्रृंखला, काटोर्सैट-3, रिसोर्ससैट-2 एवं 2ए, रीसैट-1ए, इनसैट-3डीआर एवं 3डीएस, ओशनसैट-3, सरल और निसार) से प्राप्त आंकड़े भी भारत में उपलब्ध हैं, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भी शामिल है।

परिचालन संचार उपग्रहों में से 12 उपग्रहों की कवरेज केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तक है। यह क्षमता दूरसंचार और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न सेवा प्रदाताओं को प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, 10 विदेशी उपग्रहों और 3 निम्न पृथ्वी कक्षा/मध्यम पृथ्वी कक्षा तारामंडलों को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सहित भारत में सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकरण दिया गया है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन/अंतरिक्ष विभाग के प्राकृतिक संसाधन गणना कार्यक्रम (एनआर सेंसस) के एक भाग के रूप में हिमालय और लद्दाख सहित राष्ट्रीय स्तर पर प्ाकृ तिक संसाधनों, भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण तथा बंजर भूमि की स्थिति की आवधिक निगरानी की जाती है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन/अंतरिक्ष विभाग ने हिमालयी संसाधनों, प्राकृतिक खतरों और भू-गतिकी की निगरानी के लिए "उत्तर-पश्चिम हिमालय (लद्दाख सहित) का पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र अध्ययन" किया है।

इसरो/अंतरिक्ष विभाग ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में निम्नलिखित सुदूर संवेदन अनुप्रयोग परियोजनाएं भी शुरू की हैं:

लद्दाख विशिष्ट मॉडलिंग और अंतरिक्ष अनुप्रयोग (एलएएमए): लद्दाख क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की वैज्ञानिक जांच। प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन एवं प्रबंधन के लिए एक अनुकूलित गतिशील जियोपोर्टल विकसित किया गया।

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के विकास के लिए संबद्ध डेटाबेस के साथ स्थानिक डेटा अवसंरचना (एसडीआई) जियोपोर्टल (जियो-लद्दाख): जैव-संसाधन विस्तार, कृषि और बागवानी प्रबंधन, कृत्रिम ग्लेशियरों के विकास के लिए स्थल, जल संसाधनों का संरक्षण, सौर एवं पवन ऊर्जा का संचयन, बाढ़ के खतरे का आकलन आदि।

अमृत-1.0: लेह और करगिल शहरों के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान के अति उच्च-रिजॉल्यूशन उपग्रह डेटा निर्माण का उपयोग करके बड़े पैमाने पर शहरी भू-स्थानिक डेटाबेस बनाया गया।

अमृत-2.0: लेह और करगिल शहरों के लिए जल निकाय सूचना प्रणाली का विकास।

एलयूएलसी परिवर्तन विश्लेषण: लद्दाख के लिए 2020-21 और 2025-26 के 1:50,000 पैमाने पर भूमि उपयोग एवं भूमि आवरण परिवर्तन विश्लेषण का आकलन।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन/अंतरिक्ष विभाग का आपदा प्रबंधन सहायता कार्यक्रम (डीएमएसपी) लद्दाख के हिमालयी क्षेत्र सहित राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं हेतु नोडल मंत्रालयों/विभागों को उपग्रह डेटा-आधारित इनपुट प्रदान करता है।

परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन

(जीएनएस)।

वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट तक नियोजित विस्तार से उत्पन्न होने वाले परमाणु अपशिष्ट का प्रबंधन वर्तमान अपशिष्ट प्रबंधन पद्धति के अनुरूप है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और ईंधन चक्र सुविधाओं से उत्पन्न होने वाले परमाणु अपशिष्टों का निपटान/प्रबंधन "परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962", उसके बाद के संशोधनों और परमाणु ऊर्जा (रेडियोधर्मी अपशिष्टों का सुरक्षित निपटान) नियम, 1987 के प्रावधानों के तहत सुरक्षित रूप से किया जाता है।

रेडियोधर्मी अपशिष्ट के प्रबंधन की परिचालन क्षमता और इसके अवलोकन के लिए स्वतंत्र नियामक क्षमता को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन स्थापित किया गया है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में संचालन के दौरान उत्पन्न रेडियोधर्मी अपशिष्ट निम्न और मध्यम गतिविधि स्तर के होते हैं और उनका प्रबंधन स्थल पर ही किया जाता है। इन अपशिष्टों को उपचारित, सांद्रित, संहत, सीमेंट जैसी ठोस सामग्रियों में स्थिर किया जाता है और विशेष रूप से निर्मित संरचनाओं जैसे प्रबलित कंक्रीट खाइयों और टाइल के छिद्रों के माध्यम से इनका निपटारा किया जाता है। अपशिष्ट में मौजूद रेडियोधर्मिता के प्रभावी परिसीमन की पुष्टि करने के लिए भूमिगत जल और मिट्टी के नमूनों की नियमित निगरानी करके योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए बोर-वेल की मदद से निपटान सुविधाओं पर निरंतर निगरानी रखी जाती है। यह अभ्यास अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के दिशानिर्देशों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधियों के अनुरूप है।

वर्ष 2025-26 के बजट घोषणा के बाद वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक समिति द्वारा सक्रिय रूप से विचार-विमर्श किया गया है, जिसमें परमाणु अपशिष्ट के प्रबंधन सहित सभी प्रासंगिक पहलुओं की समीक्षा की गई है। परमाणु ऊर्जा मिशन की सफलता के लिए 5 से 7 वर्ष की समय-सीमा के भीतर, नीतिगत, कानूनी और विनियामक सुधारों की दिशा में परमाणु ऊर्जा उत्पादन के सभी संबंधित क्षेत्रों में प्रयुक्त ईंधन पुनसंर्साधन और अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित अनेक गतिविधियां शामिल हैं।

आमतौर पर, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से निकलने वाले रेडियोधर्मी ठोस अपशिष्ट का निपटारा संयंत्रों के बंद होने सहित उनके संचालन तक घन मीटर/वर्ष/मेगावाट के भीतर ही किया जाता है। अपशिष्ट के निपटारे की मात्रा और स्थान के संबंध में रेडियोधर्मी अपशिष्टों का रिकॉर्ड नियमित रूप से नियामक प्राधिकरण के पास दर्ज किया जाता है। देश में विखंडनीय सामग्री की प्राप्ति और परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन के बोझ को कम करने के लिए एक बंद परमाणु ईंधन चक्र का पालन किया जाता है, जहां खर्च किए गए ईंधन को पुनः संसाधित किया जाता है और इसके अधिकांश घटकों को भविष्य के रिएक्टरों के लिए ईंधन के रूप में पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। पुनः प्रसंस्करण के दौरान उत्पन्न उच्च-स्तरीय रेडियोधर्मी अपशिष्ट को विट्रीफिकेशन द्वारा एक निष्क्रिय ग्लास मैट्रिक्स में स्थिर किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप अंतरिम भंडारण के लिए ठोस भंडारण निगरानी सुविधाओं में संग्रहीत किया जाता है। अपशिष्ट मात्रा में कमी के लिए सामाजिक अनुप्रयोग के लिए लंबे समय तक रहने वाले रेडियोधर्मी घटकों की प्राप्ति और उपयोगी रेडियोआइसोटोप के पृथक्करण/निष्कर्षण के लिए विभाजन प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान और विकास जारी है और निष्क्रिय या अल्पकालिक रेडियोधर्मी अपशिष्टों के लिए लंबे समय तक रहने वाले एक्टिनाइड्स का निपटारा करने से आने वाले दशकों में दीर्घकालिक निपटान की आवश्यकता समाप्त होने की संभावना है।

बजट 2025-26 के दौरान घोषित परमाणु ऊर्जा मिशन का उद्देश्य एसएमआर के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये का परिव्यय बनाना है जो अनुसंधान और विकास के लिए धन की आवश्यकता को पूरा करेगा। वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट के मिशन और संबंधित ईंधन चक्र गतिविधियों (परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है) को इसके कार्यान्वयन को पूरा करने के लिए अत्यधिक धनराशि की आवश्यकता होगी जिसे अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के साथ-साथ निजी वित्तपोषण द्वारा पूरा किया जाएगा।

कुलसेकरपट्टिनम स्पेसपोर्ट

(जीएनएस)।

कुलसेकरपट्टिनम स्पेसपोर्ट पर बुनियादी ढांचे के विकास की वर्तमान स्थिति, इसके पूर्ण कमीशनिंग की समय-सीमा और अब तक परियोजना के लिए आवंटित तथा उपयोग की गई धनराशि सहित:

ईस्ट-कोस्ट रोड के मार्ग परिवर्तन के लिए भूमि को छोड़कर भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है।

साइट विकास कार्य पूरा हो गया है और तकनीकी सुविधाओं के लिए निर्माण कार्य शुरू हो गया है।

विभिन्न कार्य केन्द्रों पर विभिन्न उपकरणों और संरचनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

कुलसेकरपट्टिनम स्पेसपोर्ट को वित्त वर्ष 2026-27 में चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।

कुलसेकरपट्टिनम स्पेसपोर्ट को आवंटित धनराशि झ 985.96 करोड़ रुपये।

परियोजना के लिए उपयोग की गई धनराशि झ 389.58 करोड़ रुपये (31 जुलाई 2025 तक)

पेलोड क्षमता के संदर्भ में कुलसेकरपट्टिनम प्रक्षेपण स्थल के विशिष्ट लाभ और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र एसएचएआर (एस डी एस सी-एस एच ए आर) में मौजूदा प्रक्षेपण सुविधा के साथ इसकी तुलना निम्नानुसार है:

कुलसेकरपट्टिनम प्रक्षेपण स्थल इसरो के लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी) श्रेणी के उपग्रह प्रक्षेपण यानों की पेलोड क्षमता को बढ़ाएगा और साथ ही उपग्रहों को ध्रुवीय कक्षाओं में प्रक्षेपित करेगा।

एसडीएससी शार, श्रीहरिकोटा से कार्यात्मक रूप से असाधारण सूर्य-तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षाओं (एसएसपीओ) के प्रक्षेपण के लिए भूमि पर खर्च किए गए चरणों के प्रभाव से बचने हेतु रॉकेट को गतिशील करने की आवश्यकता होती है और इससे पेलोड क्षमता में काफी कमी आएगी।

कुलसेकरपट्टिनम से प्रक्षेपण के समय एसएसएलवी से एसएसपीओ तक की पेलोड क्षमता लगभग 300 किलोग्राम है, जबकि एसडीएससी शार से प्रक्षेपण के समय उपयोगी पेलोड के लिए यह क्षमता अपर्याप्त है।

कमीशनिंग के बाद, गैर-सरकारी संस्थाओं (एनजीई) द्वारा एसएसएलवी और समकक्ष प्रक्षेपण यानों का प्रक्षेपण कुलसेकरपट्टिनम स्पेसपोर्ट से किए जाने की योजना है।

यह जानकारी आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने दी।

किसानों को वाई-फाई सुविधा का लाभ

(जीएनएस)।

आरजीआई (भारत के महापंजीयक) के आंकड़ों के अनुसार, देश के कुल 6,44,131 गांवों में से 30.06.2025 तक 6,26,055 गांवों में मोबाइल कवरेज नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट सुविधा (3जी/4जी) उपलब्ध है।

देश की सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) और गाँवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। भारतनेट के माध्यम से देश में कुल 13,01,193 एफटीटीएच कनेक्शन चालू किए जा चुके हैं। वाई-फाई तकनीक से युक्त एफटीटीएच कनेक्शन का उपयोग सभी प्रकार की ऑनलाइन सेवाओं जैसे ई-शिक्षा, ई-स्वास्थ्य, ई-गवर्नेंस, ई-कॉमर्स आदि तक पहुँचने के लिए किया जा रहा है, जिसमें किसानों द्वारा कृषि के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाने और कृषि में नए विकास के बारे में खुद को अपडेट रखने के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा है।

डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) के अंतर्गत 4जी संतृप्ति परियोजना, बॉर्डर आउट पोस्ट (बीओपी)- बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट(बीआईपी) परियोजना, भारतनेट परियोजना आदि जैसी विभिन्न परियोजनाएँ गाँवों में मोबाइल कवरेज और इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए शुरू की जा रही हैं। 4जी संतृप्ति परियोजना के अंतर्गत जून 2025 तक, देश भर में विभिन्न सरकारी वित्त पोषित मोबाइल परियोजनाओं के अंतर्गत 21,748 मोबाइल टावर चालू किए जा चुके हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए "पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना 2022-23" नामक एक पुनर्निर्धारित और विस्तारित योजना शुरू की है। राज्यों को पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना 2022-23 के भाग-श (ऑप्टिकल फाइबर केबल) के लिए कुल 3000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इस धनराशि का उपयोग वर्तमान में कवर की गई ग्राम पंचायतों से लेकर गाँवों तक भारतनेट का विस्तार करने के लिए किया जा सकता है, ताकि ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) पर सरकारी संस्थानों (जैसे स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी, पुलिस स्टेशन, कृषि विकास केन्द्र, डाकघर, राशन की दुकान आदि), निजी संस्थानों और घरों को भारतनेट नेटवर्क से जोड़ा जा सके।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएमवाणी) के तहत सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड के प्रसार हेतु दूरसंचार विभाग (डीओटी) के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। वर्तमान में, देश भर में 3,53,105 पीएमवाणी वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित हैं।

यह जानकारी संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

RNI No. GUJGUJ/2011/39228 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004, Ahmedabad,Gujarat-380 004. (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002 (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002. and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPKLAL SHAH

राजकोट मंडल में डबल ट्रैक कार्य के चलते भावनगर मंडल की कुछ ट्रेनें होंगी प्रभावित

राजकोट मंडल में स्थित लाखाबावल-पीपली-कानालुस सेक्शन में डबल ट्रैक कार्य के चलते 23 अगस्त, 2025 (शनिवार) तक रेल यातायात प्रभावित होगा। भावनगर रेलवे मंडल की प्रभावित होने वाली ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

रद्द ट्रेनें:

- ट्रेन नं 19251 ओखा-वेरावल एक्सप्रेस 20.08.2025 से लेकर 22.08.2025 तक रद्द रहेगी।
- ट्रेन नं 19252 वेरावल-ओखा एक्सप्रेस 20.08.2025 से लेकर 22.08.2025 तक रद्द रहेगी।

आंशिक रूप से रद्द की गयी ट्रेनें:

- ट्रेन नं 59206 पोरबंदर-कानालुस लोकल तत्काल प्रभाव से 22.08.2025 तक लालपुर जाम-कानालुस के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।
- ट्रेन नं 59205 कानालुस-पोरबंदर लोकल तत्काल प्रभाव से 22.08.2025 तक कानालुस-लालपुर जाम के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

ट्रेनों का स्टोपेज रद्द होना:

- ट्रेन नं 19209 भावनगर-ओखा एक्सप्रेस तत्काल प्रभाव से 23.08.2025 तक लाखाबावल स्टेशन पर नहीं रुकेगी।
- ट्रेन नं 19210 ओखा-भावनगर एक्सप्रेस तत्काल प्रभाव से 22.08.2025 तक लाखाबावल स्टेशन पर नहीं रुकेगी।

रेल यात्रियों से निवेदन है कि वे उपरोक्त फेरबदल को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा प्रारम्भ करें और ट्रेनों के परिचालन संबंधित नवीनतम अपडेटस की जानकारी के लिए www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन करें ताकि किसी प्रकार कि असुविधा ना हो।

ग्लोबल ट्रावेल एजेंट असोशिएशन (जीटीएए) के साथ भविष्य उन्मुख रेलवे पहल पर अहमदाबाद मंडल का संवाद

अहमदाबाद मंडल, पश्चिम रेलवे द्वारा दिनांक 19.08.2025 को अमदावाद में ग्लोबल ट्रावेल एजेंट असोशिएशन (GTAA) के साथ एक महत्वपूर्ण संवादात्मक एवं सहभागिता सत्र का आयोजन किया गया।

इस सत्र का उद्देश्य भारतीय रेलवे एवं ट्रैवल ट्रेड फ्रैटर्निटी के बीच एक सहयोगात्मक मंच तैयार करना था, जहाँ नए व्यापारिक अवसरों, यात्री सेवाओं, पर्यटन संवर्धन और साझेदारी के विभिन्न आयामों पर चर्चा की गई। यह पहल GTAA के उस मिशन को भी दशार्ती है जिसके अंतर्गत वह ट्रैवल इंडस्ट्री और सरकारी संस्थाओं के बीच संबंधों को सुदृढ़ कर आपसी विकास और व्यापारिक क्षितिज का विस्तार करना चाहता है।

मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश ने इस अवसर पर दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि भारतीय रेलवे केवल देश की प्रगति का आधार स्तंभ ही नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय आर्थिक विकास, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और पर्यटन संवर्धन की अहम कड़ी भी है। उन्होंने भारतीय रेलवे की दूरदर्शी नीतियों और आगामी योजनाओं की जानकारी दी—जिनमें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1377 स्टेशनों का पुनर्विकास, बुलेट ट्रेन, वंदे भारत और नमो भारत जैसी आधुनिक सेवाएँ शामिल हैं।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अन्नू त्यागी ने कहा कि भारतीय रेलवे निरंतर यात्रियों और पर्यटन क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नवोन्मेषी योजनाओं को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने डिजिटल टिकटिंग प्रणाली, मोबाइल ऐप आधारित सुविधाएँ, स्टेशन परिसरों में रेल कोच रेस्टोरेंट, प्रीमियम लाउंज, हेरिटेज टूर कियोस्क, एवं यात्रियों हेतु उबर तथा रैपिडो जैसी सेवाओं के सम्मिलन की जानकारी दी।

GTAA (ग्लोबल ट्रावेल एजेंट असोशिएशन) के प्रेसीडेन्ट श्री संकेत शाह ने भारतीय रेल की विकासोन्मुख परियोजनाओं की सराहना की और कहा कि रेलवे के व्यापक नेटवर्क और GTAA की विशेषज्ञता के संयोजन से पर्यटन एवं यात्री सेवाओं को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने विशेष रूप से स्टेशन परिसरों में विज्ञापन अवसरों, यात्री सेवा केंद्रों, प्रीमियम सुविधाओं एवं हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने जैसे क्षेत्रों में भागीदारी की संभावनाओं पर सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

मंडल प्रवक्ता ने बताया कि इस संवादात्मक सत्र में प्राप्त सभी सुझावों को भारतीय रेलवे की भविष्य की योजनाओं में शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे न केवल रेल सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता में वृद्धि होगी, बल्कि यात्रियों के अनुभव को और अधिक समृद्ध एवं संतोषजनक बनाया जा सकेगा।

यह सत्र विचारों एवं सुझावों के आदान-प्रदान का एक प्रभावी मंच सिद्ध हुआ और भारतीय रेल तथा यात्रा व्यापार समुदाय के बीच सुदृढ़ साझेदारी एवं दीर्घकालिक सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

अहमदाबाद मंडल, पश्चिम रेलवे ने पुनः यह स्थापित किया है कि वह नवाचार, उत्कृष्ट सेवा, सतत विकास और यात्रियों के कल्याण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है, और यह प्रतिबद्धता भारतीय रेल मंत्रालय की दूरदर्शी सोच तथा राष्ट्र के समग्र विकास के लक्ष्यों के अनुरूप है।

पश्चिम रेलवे चलाएगी और दो जोड़ी गणपति स्पेशल ट्रेन

मुंबई, 20 अगस्त, 2025

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा गणपति के त्योहारी सीजन के दौरान उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से उधना – रत्नागिरी और विश्वामित्री – रत्नागिरी स्टेशनों के बीच विशेष किराए पर और 2 जोड़ी गणपति स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है:

1. ट्रेन संख्या 09022/09021 उधना-रत्नागिरी साप्ताहिक स्पेशल [6 फेरे]

ट्रेन संख्या 09022 उधना-रत्नागिरी स्पेशल प्रत्येक गुरुवार को उधना से 10:00 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन 20:00 बजे रत्नागिरी पहुँचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09021 रत्नागिरी-उधना स्पेशल प्रत्येक गुरुवार को रत्नागिरी से 21:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 10:20 बजे उधना पहुँचेगी। उपर्युक्त जोड़ी ट्रेनें 21 अगस्त से 4 सितंबर, 2025 तक चलेंगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में वलसाड, वापी, दहानू रोड, पालघर, वसई रोड, भिवंडी रोड, पनवेल, पेन, रोहा, मानगांव, वीर, खेड़, चिपलून और संगमेश्वर रोड स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में स्लीपर क्लास और द्वितीय श्रेणी के सामान्य डिब्बे हैं।

2. ट्रेन संख्या 09120/09119 विश्वामित्री – रत्नागिरी साप्ताहिक स्पेशल [6 फेरे]

ट्रेन संख्या 09120 विश्वामित्री – रत्नागिरी स्पेशल प्रत्येक सोमवार को विश्वामित्री से 08:00 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन 20:00 बजे रत्नागिरी पहुँचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09119 रत्नागिरी – विश्वामित्री स्पेशल प्रत्येक सोमवार को रत्नागिरी से 21:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 11:45 बजे विश्वामित्री पहुँचेगी। उपर्युक्त जोड़ी ट्रेनें 25 अगस्त और 8 सितंबर, 2025 तक चलेंगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में भरूच, सूरत, वलसाड, वापी, दहानू रोड, पालघर, वसई रोड, भिवंडी रोड, पनवेल, पेन, रोहा, मानगांव, वीर, खेड़, चिपलून और संगमेश्वर रोड स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास और द्वितीय श्रेणी के सामान्य डिब्बे हैं।

ट्रेन संख्या 09022 एवं 09120 की बुकिंग पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू है। ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 का किया सफल परीक्षण, 7,000 किमी. से अधिक दूर करेगी वार

(जीएनएस)।

भारत ने बुधवार को ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 'अग्नि-5' का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस परीक्षण से भारत के रक्षा क्षेत्र को बड़ी मजबूती मिली है।

सरकार ने बताया कि मिसाइल ने सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को सफलतापूर्वक सत्यापित किया। यह परीक्षण सामरिक बल कमान की देखरेख में किया गया, जैसा कि रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में पुष्टि की।

यह मिसाइल अग्नि-5 का एक उन्नत संस्करण है, जो भारत की अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) है। इसकी मारक क्षमता 7,000 किलोमीटर से अधिक है। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने विकसित किया है।

पिछले साल, भारत ने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल रीएंट्री व्हीकल (MIRV) क्षमता वाली अग्नि-5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया था। यह तकनीक हथियार प्रणाली को एक साथ कई परमाणु हथियारों से निपटने में सक्षम बनाती है।

जून में यह रिपोर्ट आई थी कि DRDO इसकी मारक क्षमता को 7,500 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन में शामिल DRDO के वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की थी।11 मार्च 2024 को भारत ने तमिलनाडु के कलपक्कम से अग्नि-5 का पहला एमआईआरवी परीक्षण प्रक्षेपण किया था। इस परीक्षण ने एक साथ कई वारहेड ले जाने और छोड़ने की इसकी क्षमता को मान्य किया।

यह मिसाइल एक साथ तीन परमाणु वारहेड तक ले जाने और फायर करने में सक्षम है। भविष्य में इसमें बंकर-बस्टर बम तकनीक को एकीकृत करने का लक्ष्य है, जिससे बंकर जैसे मजबूत लक्ष्यों के खिलाफ इसकी मारक क्षमता बढ़ेगी।

भारत के इस परीक्षण से पाकिस्तान में चिंता बढ़ गई है। पाकिस्तान स्थित थिंक टैंक स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट (एसवीआई) ने प्रधान मंत्री शाहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर को चेतावनी दी है कि भारत का मिसाइल कार्यक्रम क्षेत्रीय स्थिरता के लिए "गंभीर जोखिम" पैदा करता है।

एसवीआई ने बताया कि 2016 में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम (एमटीसीआर) में शामिल होने के बाद भारत के मिसाइल विकास में तेजी आई, जिससे उसे उन्नत प्रणालियों तक पहुंच मिली। थिंक टैंक ने चेतावनी दी कि भविष्य के संस्करण 8,000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता के साथ वाशिंगटन, मॉस्को और बीजिंग जैसे दूर के शहरों को भी निशाना बना सकते हैं।

कोयला मंत्रालय कल वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के 13वें दौर का शुभारंभ करेगा

(जीएनएस)।

कोयला मंत्रालय 21 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के 13वें दौर का शुभारंभ करने वाला है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी मुख्य अतिथि और कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

यह आयोजन भारत के कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम होगा। वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी प्रक्रिया के प्रत्येक दौर में स्थापित और नए उद्योग जगत के दिग्गजों की मजबूत भागीदारी देखी गई है। इसका उद्देश्य कोयला उत्पादन में तेजी लाना और देश की बढ़ती ऊर्जा मांग के लिए पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है। आगामी 13वें दौर में खदानों की पेशकश सबसे उदार शर्तों पर जारी रहेगी, जिससे व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा मिलेगा और विभिन्न हितधारकों से निवेश आकर्षित होगा।

स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों को कम करने के लिए विशेष अभियान 5.0 के लिए तैयारी बैठक आयोजित

(जीएनएस)।

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने आज विशेष अभियान 5.0 के लिए पहली तैयारी बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता डीएआरपीजी के सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने की और इसमें डाक, कोयला, शिक्षा, संस्कृति आदि मंत्रालयों सहित 84 मंत्रालयों/विभागों के 200 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

विशेष अभियान 5.0, 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य सभी सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देना, रिकॉर्ड प्रबंधन को मजबूत करना और मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और क्षेत्रीय कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करना है। बैठक के दौरान, डीएआरपीजी ने विशेष अभियान 5.0 के लिए दिशानिर्देश प्रस्तुत किए।

यह अभियान दो चरणों में लागू किया जाएगा -प्रारंभिक चरण 16 से 30 सितंबर, 2025 तक और कार्यान्वयन चरण 2 से 31 अक्टूबर, 2025 तक। विशेष अभियान 5.0 का शुभारंभ कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा सितंबर 2025 में किया जाएगा।

विशेष अभियान 5.0 मंत्रालयों/विभागों, संबद्ध/ अधीनस्थ/ स्वायत्त कार्यालयों, विदेशी मिशनों और केन्द्रों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, रक्षा प्रतिष्ठानों, रेलवे/डाकघरों आदि के सार्वजनिक स्थानों में स्वच्छता पर केंद्रित होगा। यह अभियान संसदीय आश्वासनों, वीआईपी संदर्भों, राज्य सरकार के संदर्भों, मंत्रालयों के बीच के संदर्भों, पीएमओ संदर्भों और लोक शिकायतों में लंबित मामलों को कम करने पर केंद्रित होगा। इसके साथ ही, सीएसएमओपी 2022 के तहत अभिलेख प्रबंधन का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा। अभियान की प्रगति की निगरानी स्पेशल कैंपेन डिजिटल मॉनिटरिंग पोर्टल (एससीडीपीएम) के माध्यम से की जाएगी, जिसकी साप्ताहिक समीक्षा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव की अध्यक्षता में की जाएगी।

2021 में अपनी शुरूआत के बाद से, यह विशेष अभियान प्रतिवर्ष लागू किया गया है, जिसमें 12 लाख से अधिक कार्यालयों को शामिल किया गया है, 696.27 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान मुक्त किया गया है, 137.86 लाख फाइलों का निपटान किया गया है और कबाड़ निपटान से ₹3296.71 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है।

शहरों में दोहरी गर्मी और अत्यधिक वर्षा का सामना करना पड़ रहा

(जीएनएस)।

सरकार आईपीई ग्लोबल और ईएसआरआई इंडिया की हालिया रिपोर्ट से अवगत है, जिसमें पाया गया है कि भारत के शहरों में 2030 तक हीटवेव के दिनों में दोगुनी वृद्धि और अत्यधिक वर्षा की घटनाओं में वृद्धि होगी। इसमें खुलासा किया गया है कि 2030 तक जलवायु परिवर्तन से भारत भर में अत्यधिक वर्षा की घटनाओं की तीव्रता में 43% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे देश अधिक गर्म और आर्द्र हो जाएगा।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) शहरी क्षेत्रों सहित भारत के विभिन्न स्थानों पर, स्टेशन और शहर-आधारित मौसम संबंधी आंकड़ों का उपयोग करके, लू और भारी वर्षा जैसी चरम मौसम घटनाओं की निरंतर निगरानी करता है। इसके अलावा, आईएमडी द्वारा उपलब्ध कराए गए ग्रिडेड वर्षा (25 किमी रिजॉल्यूशन) और तापमान डेटा (50 किमी रिजॉल्यूशन) का भी इन चरम घटनाओं पर नजर रखने के लिए उपयोग किया जाता है। पिछले 11 वर्षों में विभिन्न उप-मंडलों में लू के दिनों की वर्षवार संख्या अनुलग्नक-1 में दी गई है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के सहयोग से, जलवायु खतरों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों हेतु जोखिम आकलन और प्रभाव-आधारित पूर्वानुमान के लिए दृष्टिकोण प्रदान करता है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) पूरे देश में केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को समान रूप से क्रियान्वित करता है; इसलिए, धन का आवंटन राज्यवार नहीं होता है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से राज्य सरकारों को सीधे धनराशि जारी नहीं की जाती है।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के पास राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) और राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) के माध्यम से सहायता हेतु संसाधन उपलब्ध हैं। यदि राज्यों की ओर से वित्तीय सहायता का अनुरोध प्राप्त होता है, तो केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) के लिए प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुसार उस पर विचार करती है।

राज्य सरकार, कुछ निर्धारित शर्तों और मानदंडों की पूर्ति के अधीन, एसडीआरएफ के वार्षिक निधि आवंटन के 10% तक का उपयोग उन प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए कर सकती है, जिन्हें वे राज्य में स्थानीय संदर्भ में 'आपदा' मानते हैं और जो प्राकृतिक आपदाओं की केंद्रीय अधिसूचित सूची में शामिल नहीं हैं।

अगली पीढ़ी के चौथे अपतटीय गश्ती पोत के निर्माण की आधिकारिक शुरूआत

भारतीय तटरक्षक बल के लिए अगली पीढ़ी के चौथे अपतटीय गश्ती पोत के निर्माण की आधिकारिक शुरूआत मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में इस्पात काटने के समारोह साथ की गई

(जीएनएस)।

भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) के लिए मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) द्वारा निर्मित किए जा रहे छह अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोतों (एनजीओपीवी) की श्रृंखला में चौथे जहाज यार्ड 16404 हेतु इस्पात काटने का समारोह 20 अगस्त, 2025 को मुंबई में आयोजित हुआ। स्वदेशी तकनीक से अभिकल्पित, विकसित एवं निर्मित ये 117 मीटर लंबे जहाज 23 नॉट तक की गति से चल सकते हैं और इनकी परिचालन सीमा 5,000 समुद्री मील है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-आधारित पूर्वानुमानित रखरखाव प्रणाली, रिमोट पायलटेड ड्रोन, इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम और एकीकृत प्लेटफार्म प्रबंधन प्रणाली सहित उन्नत प्रौद्योगिकियों से लैस अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत भारत के विशाल समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए भारतीय तटरक्षक की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएंगे। इसमें 11 अधिकारियों और 110 कर्मियों के रहने की क्षमता भी होगी। 20 दिसंबर, 2023 को ह्यखरीदें (भारतीय-आईडीडीएम)ह्व श्रेणी के तहत अनुबंधित अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत परियोजना सरकार के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से मेल खाती है।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उप महानिदेशक (तकनीकी), मुख्यालय भारतीय तटरक्षक पूर्वी समुद्र तट, महानिरीक्षक एनजी रवींद्रन ने की, जिसमें मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स के कार्यकारी निदेशक (जहाज निर्माण), श्री ए. विनोद और भारतीय तटरक्षक तथा मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। यह पहल भारत की बढ़ती रक्षा विनिर्माण शक्ति एवं आत्मनिर्भरता के प्रति सरकार के अटूट विश्वास को प्रदर्शित करती है। यह भारतीय तटरक्षक बल को राष्ट्रीय समुद्री हितों की अधिक प्रभावशीलता के साथ सुरक्षा करने के लिए सशक्त भी बनाती है।

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम, हरियाणा सरकार को हिसार में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) विकसित करने में सहायता करेगा

हिसार में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर से 32,417 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होगा और 1.25 लाख रोजगार सृजित होंगे

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम, हिसार में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) के विकास में हरियाणा सरकार का सहयोग करेगा। अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा (एकेआईसी) ने आज राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी), हरियाणा सरकार और हरियाणा हवाई अड्डा विकास निगम (एचएडीसी) के बीच राज्य समर्थन समझौते (एसएसए) और शेयरधारक समझौते (एसएचए) पर हस्ताक्षर किए।

ये समझौते, हरियाणा में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने और विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए भारत सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दशार्ते हैं। इसकी शुरूआत हिसार में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) के विकास से होगी। स्थानीय विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करके और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय निवेश को प्रोत्साहित करके, एकेआईसी मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाने और भारत को और अधिक आत्मनिर्भर और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

हरियाणा में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) हिसार के राज्य में आर्थिक विकास का एक प्रमुख संचालक बनने की संभावना है। इसके विकास से व्यापार-अनुकूल वातावरण को प्रोत्साहन मिलेगा, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा और एक प्रमुख औद्योगिक स्थल के रूप में हरियाणा की स्थिति और मजबूत होगी। इस क्लस्टर से भारत और दुनिया भर के निवेशकों की महत्वपूर्ण रुचि आकर्षित होने की संभावना है, जिससे देश के विनिर्माण क्षेत्र को काफी प्रोत्साहन मिलेगा।

2,988 एकड़ में फैला आईएमसी हिसार, हरियाणा के हिसार में नवनिर्मित महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। 32,417 करोड़ रुपये की निवेश क्षमता और 4,680 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ, इससे 1.25 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है। ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी के बीच रणनीतिक रूप से स्थित, यह एनएच-52, एनएच-09, रेल संपर्क और प्रमुख लॉजिस्टिक्स केंद्रों के निकटता के माध्यम से उत्कृष्ट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। उन्नत बुनियादी ढांचे और हिसार शहर के निकटता के साथ, यह आईएमसी हरियाणा और उत्तर भारत के औद्योगिक भविष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने के लिए तैयार है।

इन समझौतों पर एनआईसीडीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, श्री रजत कुमार सैनी; हरियाणा सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग की आयुक्त एवं सचिव, श्रीमती अमनीत पी. कुमार; और हरियाणा सरकार के एचएडीसी के प्रबंध निदेशक, श्री नरहरि सिंह बांगर ने हस्ताक्षर किए। यह भविष्य के अनुकूल सहयोग इन औद्योगिक समूहों के विकास की नींव रखता है जो अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत रणनीतिक केंद्रों के रूप में कार्य करेंगे और भारत के एक अग्रणी वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने के दृष्टिकोण में योगदान देंगे।

स्वदेश में डिजाइन सक्षम-3000 एक उच्च-प्रदर्शन स्विच-कम-राउटर

(जीएनएस)।

सक्षम-3000 एक उच्च-प्रदर्शन स्विच-कम-राउटर है, जिसे दूरसंचार विभाग की अनुसंधान एवं विकास शाखा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। यह 25.6 टेराबिट प्रति सेकंड की स्विचिंग क्षमता प्रदान करता है और विभिन्न प्रकार के नेटवर्क कनेक्शनों को सपोर्ट करता है। यह उपकरण मानक उपकरण रैक में फिट होने के लिए बनाया गया है और इसमें विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित करने वाली विशेषताएँ शामिल हैं, जैसे बैकअप पावर सप्लाई और कूलिंग फैन जिन्हें सिस्टम को बंद किए बिना बदला जा सकता है। इसे लचीलेपन के लिए डिजाइन किया गया है, जो नेटवर्क फंक्शंस और संचार विधियों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करता है। ये क्षमताएँ इसे आधुनिक डिजिटल नेटवर्क में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाती हैं, जहाँ उच्च प्रदर्शन, विश्वसनीयता और अनुकूलनशीलता आवश्यक है। सक्षम-3000 का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोग क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, जिसमें डेटा केंद्रों में लीफ स्विच, स्पाइन स्विच या सुपर-स्पाइन स्विच के रूप में तैनाती, साथ ही दूरसंचार और आईपी नेटवर्क में एज राउटर या कोर राउटर के रूप में कार्य करना शामिल है। बड़े उद्यमों और दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा सक्षम-3000 तकनीक के व्यावसायिक उपयोग और अपनाने को सक्षम बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बड़े पैमाने पर विनिर्माण और उपयोग के लिए उत्पादन तकनीक पहले ही एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) भागीदार, मेसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) को हस्तांतरित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, इस उत्पाद को विभिन्न दूरसंचार उत्पाद प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किया जा रहा है जहाँ सी-डॉट भाग ले रहा है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल सीएम सिक्योरिटी स्टाफ परिवार की ओर से आयोजित सत्यनारायण कथा-महापूजा में श्रद्धाभाव से उपस्थित रहे

पवित्र श्रावण मास के अवसर पर गांधीनगर में हुआ आयोजन

गांधीनगर, 20 अगस्त : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल बुधवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री सिक्योरिटी स्टाफ परिवार की ओर से पवित्र श्रावण मास के अवसर पर आयोजित सत्यनारायण कथा-महापूजा में श्रद्धाभाव से उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री एम.के. दास, सचिव डॉ. विक्रांत पांडेय और पुलिस अधीक्षक, सीएम सुरक्षा श्री चिंतन तैरैया, उप पुलिस अधीक्षकों और मुख्यमंत्री के सुरक्षा अधिकारियों सहित कमांडो भी इस कथा श्रवण और पूजा-आरती में शामिल हुए।

डीपीडीपी अधिनियम, 2023 आरटीआई के तहत पारदर्शिता बनाए रखते हुए गोपनीयता को बरकरार रखता है

(जीएनएस)।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीपी अधिनियम) डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए इस तरह से प्रावधान करता है जो व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के अधिकार और वैध उद्देश्यों के लिए ऐसे व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता, दोनों को मान्यता देता है।

डीपीडीपी अधिनियम एक विस्तृत और व्यापक सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया के बाद पारित किया गया था, जिसके दौरान डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2022 (डीपीडीपी विधेयक) पर 22,600 से अधिक टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं। इन सुझावों पर सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श के बाद, डीपीडीपी विधेयक संसद में पेश किया गया और बाद में डीपीडीपी अधिनियम, 2023 के रूप में अधिनियमित किया गया।

डीपीडीपी अधिनियम के माध्यम से आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(जे) में संशोधन, निजता के मौलिक अधिकार को सूचना के अधिकार के साथ जैसा कि न्यायमूर्ति केएस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी, संतुलित करता है। यह संशोधन उचित प्रतिबंधों पर स्थापित न्यायिक तर्क के अनुरूप है, मौजूदा न्यायशास्त्र को संहिताबद्ध करता है, और कानूनों के बीच संभावित टकराव से बचने में मदद करता है।

इसके अलावा, आरटीआई अधिनियम की धारा 8(2) के तहत, कोई सार्वजनिक प्राधिकरण सूचना तक पहुँच की अनुमति दे सकता है यदि सूचना के प्रकटीकरण में जनहित अधिक हो, संरक्षित हितों को होने वाले नुकसान से । यह धारा इस प्रकार है:

'आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 (1923 का 19) में किसी बात के होते हुए भी या उपधारा (1) के अनुसार अनुमेय किसी छूट के होते हुए भी, कोई सार्वजनिक प्राधिकरण सूचना तक पहुंच की अनुमति दे सकता है, यदि प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित अधिक है संरक्षित हितों को होने वाले नुकसान से ।'

उक्त संशोधन व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण पर प्रतिबंध नहीं लगाता; बल्कि, यह व्यक्तियों के निजता के अधिकार और सूचना के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पारदर्शिता ढाँचा और सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजता ढाँचा, पारदर्शिता और निजता के बीच संतुलन बनाए रखते हुए, सामंजस्यपूर्ण रूप से अस्तित्व में बने रहें।

जैसा कि अधिनियम के समय भी किया गया था, सरकार ने नियमों के लिए भी विभिन्न मीडिया संगठनों के साथ विचार-विमर्श सहित व्यापक परामर्श किया है।

यह जानकारी आज केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में प्रस्तुत की।

खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के उद्घाटन संस्करण में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष एथलीट 24 स्वर्ण पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे

जम्मू और कश्मीर की डल झील में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की ओपन-एज जल क्रीड़ा प्रतियोगिता में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरल शीर्ष राज्यों में शामिल

(जीएनएस)।

जम्मू और कश्मीर की प्रतिष्ठित डल झील में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव (केआईडब्ल्यूएसएफ) में देश के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलीट 24 स्वर्ण पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। तीन दिवसीय इस आयोजन में 400 से ज्यादा एथलीट नौकायन, कैनोइंग और कयाकिंग जैसी स्पधाओं में पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।

खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 पहली समेकित ओपन-एज श्रेणी चैंपियनशिप होगी जिसमें सभी 14 कयाकिंग और कैनोइंग स्पधाएँ और 10 रोइंग स्पधाएँ ओलंपिक स्पधाएँ होंगी। वाटर गेम्स के आकर्षण को और बढ़ाने के लिए, तीन प्रदर्शन स्पधाएँ होंगी - वाटर स्कीइंग, शिखर बोट स्प्रिंग और ड्रैगन बोट रेस।

इस महोत्सव में 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हिस्सा लेंगे। इनमें से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और केरल के एथलीटों पर सबकी नजरें होंगी।

प्रतियोगिता प्रबंधक, पूर्व विश्व कप विजेता कैनोइस्ट और ओलंपिक जज, बिलकिस मीर ने कहा, "चूँकि सर्विसेज इन खेलों में एक टीम के रूप में भाग नहीं लेंगी, इसलिए यह देखना अच्छा होगा कि राज्य कैसा प्रदर्शन करते हैं। कोर्स को सभी अंतरराष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और हम पूरी तरह तैयार हैं।"

खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, खेलो इंडिया कैलेंडर में एक नया आयोजन है। 2025 में, दो नए आयोजन जोड़े गए हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स मई में दीव में आयोजित किए गए थे। खेलो भारत नीति के अनुसार, वाटर गेम्स और बीच गेम्स, दोनों का उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना और पर्यटन को आकर्षित करना है।

कयाकिंग और कैनोइंग के लिए, नवंबर में टिहरी (उत्तराखंड) में आयोजित पिछली राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को क्वालीफायर के रूप में इस्तेमाल किया गया है। एकल और युगल में शीर्ष 15 और शीर्ष आठ चार खिलाड़ी केआईडब्ल्यूएसएफ में भाग लेंगे। रोइंग के लिए, इस वर्ष मार्च में भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के शीर्ष आठ खिलाड़ी भाग लेंगे।

इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी अपना शानदार प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने वाले सेना के रोवर अर्जुन लाल जाट मुख्य आकर्षणों में से एक होंगे। 28 वर्षीय जाट ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लिया है और हांग्जो में 2022 एशियाई खेलों में लाइट- वेट डबल स्कल्स में रजत पदक जीता है।

वाटर स्पोर्ट्स में पुरुषों और महिलाओं का लगभग बराबर प्रतिनिधित्व होगा। पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले 409 एथलीटों में से 202 महिलाएँ होंगी। केआईडब्ल्यूएसएफ 2025 में मध्य प्रदेश (44), हरियाणा (37), ओडिशा (34) और केरल (33) का सबसे बड़ा दल होगा। गुजरात, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल की टीमें सबसे छोटी होंगी।

गुरुवार को पहले दिन कयाकिंग और कैनोइंग स्पर्धा में खिलाड़ी तीन स्वर्ण पदकों के लिए खेलेंगे। सभी 10 रोइंग फाइनल 23 अगस्त को अंतिम दिन निर्धारित हैं। उद्घाटन समारोह गुरुवार शाम 6 बजे से शुरू होगा, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा खडसे और जम्मू- कश्मीर के अन्य गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने की उम्मीद है।

यह वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव, गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के बाद, जम्मू-कश्मीर में दूसरा खेलो इंडिया आयोजन होगा। 2017- 18 में शुरू किए गये खेलो इंडिया खेल अभियान जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का एक मिशन है और इसका उद्देश्य संगठित प्रतिभाओं की पहचान, संरचित खेल प्रतियोगिताओं और बुनियादी ढाँचे के विकास पर भी केंद्रित है।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की उपेक्षा

(जीएनएस)।

केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्यमंत्री श्री दुगार्दास उइके ने आज श्री संदीप कुमार पाठक के अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए राज्यसभा को बताया कि 15 नवंबर 2023 को, माननीय प्रधानमंत्री ने 18 राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) शुरू किया। मिशन का उद्देश्य 3 वर्षों में उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए लोगों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुँच, सड़क और दूरसंचार संपर्क, अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को 9-लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 उपायों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। अभियान के तहत प्रत्येक मंत्रालय उसे सौंपे गए उपायों को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है।

पीएम जनमन के कार्यान्वयन के मद्देनजर, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/विभागों के माध्यम से पीएम गति शक्ति मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से आवास स्तर पर डेटा संग्रह का कार्य शुरू किया है ताकि पीएम जनमन के तहत गांवों और बस्तियों में रहने वाली पीवीटीजी आबादी को कवर करने के लिए पीवीटीजी आबादी के आंकड़ों और बुनियादी ढांचे के अंतरों का अनुमान लगाया जा सके।

इसके अलावा, राज्य सरकारों के साथ समन्वय से, आईईसी शिविरों का आयोजन किया गया है, जिनका उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जन धन बैंक खाता जैसे बुनियादी दस्तावेजों को तैयार करने में सुविधा प्रदान करना है, जो आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा आदि सहित विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं।

कर्नाटक में जनजातीय संग्रहालयों की स्थापना

(जीएनएस)।

केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्यमंत्री श्री दुगार्दास उइके ने आज डा. धर्मस्थल वीरेंद्र हेग्गडे के अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए राज्यसभा को बताया कि वर्तमान में, जनजातीय कार्य मंत्रालय में किसी भी केंद्र प्रायोजित योजना के तहत कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़ या कोडागु जिलों में जनजातीय संग्रहालय या सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालाँकि, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार केंद्रीय प्रायोजित योजना ह्यजनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायताह्ल के तहत जनजातीय अनुसंधान संस्थान, कर्नाटक सहित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों (यूटी) में 29 जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत, अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं, अनुसंधान एवं प्रलेखन गतिविधियों, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, जनजातीय उत्सवों के आयोजन, विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यात्राओं और जनजातीय लोगों के आदान-प्रदान दौरों के आयोजन से संबंधित प्रस्तावों को सुनियोजित किया जाता है ताकि उनकी सांस्कृतिक प्रथाओं, भाषाओं और रीति-रिवाजों का संरक्षण और प्रसार किया जा सके। जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) मुख्य रूप से राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाली संस्थाएँ हैं।

गांधीनगर में 'सहकार से समृद्धि'के अंतर्गत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सहकारी नेताओं की एक दिवसीय कार्यशाला

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया के समक्ष सहकारी क्षेत्र का श्रेष्ठ मॉडल प्रस्तुत कर 'सहकार से समृद्धि'के जरिए देश को आगे रखेगा : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

जिला मध्यस्थ सहकारी बैंकों, दूध उत्पादक सहकारी संघों, खेती बैंक और गुजकोमासोल सहित अन्य सहकारी संस्थाओं के नेता सहभागी हुए

गांधीनगर, 20 अगस्त : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने यह स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया के समक्ष सहकारी क्षेत्र का श्रेष्ठ मॉडल प्रस्तुत कर आने वाले समय में सहकारिता क्षेत्र में भी देश को आगे रखेगा।

उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 'सहकारिताएं एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं'थीम के साथ मनाया जा रहा है। इस संदर्भ में बुधवार को गांधीनगर में 'सहकार से समृद्धि'के अंतर्गत जिला मध्यस्थ सहकारी बैंकों, दूध उत्पादक सहकारी मंडलियों, खेती बैंक और गुजकोमासोल सहित अन्य सहकारी संस्थाओं के अग्रणियों की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस कार्यशाला में अध्यक्षीय संबोधन देते हुए कहा कि स्वतंत्रता से पहले गुजरात के दो सपूत महात्मा गांधी और सरदार पटेल की अगुवाई में हुए असहयोग आंदोलन में अग्रणी रहा गुजरात आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और प्रथम सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में 'सहकार से समृद्धि'और 'वोकल फॉर लोकल'के विजन को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि अंतिम छोर के व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा में लाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहकारी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विशेष रूप से प्राथमिक सहकारी मंडलियां इसके लिए और स्वदेशी से आत्मनिर्भरता का उचित प्लेटफॉर्म है।

इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत को 140 करोड़ भारतवासियों का संकल्प और जनांदोलन बनाया है।

भारतीय तटरक्षक बल और वियतनाम तटरक्षक बल के बीच छठी उच्च स्तरीय बैठक हनोई में आयोजित हुई

(जीएनएस)।

भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) और वियतनाम तटरक्षक बल (वीसीजी) के बीच छठी उच्च स्तरीय बैठक (एचएलएम) तटरक्षक सहयोग पर 2015 के समझौता ज्ञापन के ढांचे के तहत 20 अगस्त, 2025 को वियतनाम के हनोई में आयोजित की गई। यह चर्चा समुद्री खोज एवं बचाव, समुद्री कानून प्रवर्तन, समुद्री प्रदूषण कार्रवाई और क्षमता निर्माण में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित थी। बातचीत में तस्करी, मानव तस्करी और अवैध मछली पकड़ने सहित अंतरराष्ट्रीय समुद्री अपराधों से निपटने पर विशेष ध्यान दिया गया।

इस बैठक की सह-अध्यक्षता भारतीय तटरक्षक बल के अपर महानिदेशक आनंद प्रकाश बडोला और वियतनाम तटरक्षक बल के वाइस कमांडेंट मेजर जनरल वु टुंग किएन ने की। दोनों पक्षों ने हाल की जहाजी यात्राओं और व्यावसायिक आदान-प्रदान की समीक्षा की तथा आपसी सहभागिता को विस्तार देने के लिए संयुक्त पहल जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। प्रतिनिधिमंडलों ने समुद्री सुरक्षा व समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए समन्वित एसएआर संचालन और संयुक्त प्रदूषण प्रतिक्रिया तंत्र के महत्व को भी रेखांकित किया।

दोनों देशों के तटरक्षकों ने नियमित संस्थागत बातचीत, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों के आदान-प्रदान और जहाजी यात्राओं के प्रति अपनी वचनबद्धता की पुष्टि करते हुए इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के जुड़ाव से आपसी विश्वास व परिचालन तालमेल को बढ़ावा मिलता है। बैठक में क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा, संरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मैत्री एवं सहयोग की भावना से मिलकर कार्य करने के उनके साझा संकल्प को प्रतिबिंबित किया गया।

गहरे समुद्र में अन्वेषण: तीन व्यक्तियों को 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने हेतु मानव पनडुब्बी (मत्स्य-6000) का डिजाइन और एकीकरण पूरा

(जीएनएस)।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी), चेन्नई द्वारा डीप ओशन मिशन के तहत, तीन व्यक्तियों को 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने हेतु मानव पनडुब्बी (मत्स्य-6000) का डिजाइन और एकीकरण पूरा कर लिया गया है। मत्स्य-6000 के वेट हार्बर परीक्षण जनवरी-फरवरी 2025 में तमिलनाडु के पास कट्टुपल्ली में एलएंडटी शिपबिल्डिंग फैसिलिटी में सफलतापूर्वक आयोजित किए गए।

मत्स्य-6000 को वैज्ञानिक पे-लोड में शामिल करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि जैव विविधता और गहरे समुद्र के खनिजों सहित गहरे समुद्र में सजीव और निर्जीव संसाधनों के लिए भारत की वैज्ञानिक अन्वेषण और अवलोकन गतिविधियों के साथ तालमेल बिठाया जा सके।

मत्स्य-6000 के लिए विकसित तकनीकी नवाचारों में वास्तविक समय चालक दल के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए एक बायो-वेस्ट, आपातकालीन परिदृश्यों के दौरान सहायता के लिए एक संज्ञानात्मक डिजिटल ट्विन, एक पानी के नीचे ध्वनिक टेलीफोन, मानव-रेटेड आपातकालीन गिट्टी प्रबंधन प्रणाली जो पनडुब्बी के साथ-साथ एक जहाज से भी संचालित करने में सक्षम है, एक वेल्डेड टाइटेनियम मिश्र धातु एक्सो-संरचना, मल्टी-रिंग कॉनफि गरेशन के साथ एक 80 मिमी मोटी इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डेड टाइटेनियम मिश्र धातु कार्मिक क्षेत्र और प्रणोदन के लिए उच्च घनत्व लिथियम-पॉलिमर-आधारित मुख्य बिजली प्रणाली के साथ हाइड्रोस्टेटिक रूप से स्थिर और हाइड्रोडायनामिक रूप से कुशल उप-प्रणालियां शामिल हैं। भारत-फ्रांस साझेदारी के एक भाग के रूप में, एनआईओटी के वैज्ञानिकों ने अगस्त 2025 में फ्रांसीसी समुद्री संस्थान आईएफआरईएमईआर द्वारा विकसित पनडुब्बी नॉटाइल पर सवार होकर गहरे समुद्र में मानव वैज्ञानिक अभियानों में भाग लिया और अटलांटिक महासागर में 5000 मीटर की गहराई तक गहरे समुद्र में परिचालन अनुभव और कार्यात्मक संचालन प्राप्त किया। मत्स्य-6000 का डिजाइन और विकास पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एनआईओटी, चेन्नई द्वारा पूरा किया गया है। मत्स्य-6000 के टाइटेनियम कार्मिक क्षेत्र का निर्माण इसरो के साथ एक स्वदेशी प्रयास के रूप में शुरू किया गया है। बेस फ्रेम और प्रेशर केस जैसे उप-घटक भारतीय उद्योग भागीदारों के साथ विकसित किए गए हैं। डीआरडीओ के साथ मिलकर इनरशियल नेविगेशन सिस्टम और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, डॉपलर वेलोसिटी लॉग्स, डेप्थ और एकॉस्टिक पोजिशनिंग सिस्टम और एक अंडरवाटर एकॉस्टिक टेलीफोन के साथ एकीकरण का कार्य किया जा रहा है। यह जानकारी आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग डॉ. जितेंद्र सिंह ने दी।

परम रुद्र ने आत्मनिर्भर भारत में सफलता हासिल की:

राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन 37 प्रणालियों, 40 पेटाफ्लॉप्स क्षमता के साथ भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बना रहा है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के 10,000 से अधिक शोधकताओं को सहायता मिल रही है

परम रुद्र ने आत्मनिर्भर भारत में सफलता हासिल की: भारत ने उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वदेशी सुपर कंप्यूटर और एचपीसी सर्वर का डिजाइन, विकास और निर्माण किया

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन (एनएसएम) की शुरूआत भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2015 में 4,500 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ की गई थी। इसका उद्देश्य शोधकताओं को अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटिंग सुविधाओं तक पहुँच प्रदान कर, बड़ी चुनौतियों का समाधान करके, निवेश को अनुकूलित करके और सुपर कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकियों के प्रमुख क्षेत्रों में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाकर सुपर कंप्यूटिंग में आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करना है।

एनएसएम का क्रियान्वयन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा पुणे स्थित उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (सी- डैक) और बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) के माध्यम से संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस मिशन को वर्तमान में 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

सुपर कंप्यूटरों की तैनाती और उपयोग

12 अगस्त 2025 तक, एनएसएम के अंतर्गत 40 पेटाफ्लॉप की कुल कंप्यूटिंग क्षमता वाले 37 सुपर कंप्यूटर स्थापित किए जा चुके हैं। ये प्रणालियाँ भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), आईआईटी, सी-डैक, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं जैसे अग्रणी संस्थानों और देश भर के टियर-क्क और टियर-क्कक शहरों के कई शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान संगठनों में स्थापित की गई हैं। इन प्रणालियों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है, जिनमें से अधिकांश 85% से अधिक क्षमता पर और कई 95% से अधिक क्षमता पर चल रही हैं।

इन सुपर कंप्यूटरों ने 200 से अधिक शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के 1,700 से अधिक पीएचडी विद्वानों सहित 10,000 से अधिक शोधकताओं को सहायता प्रदान की है। इन्होंने औषधि खोज, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु मॉडलिंग, खगोल विज्ञान, कम्प्यूटेशनल रसायन विज्ञान, द्रव गतिकी और पदार्थ अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक करोड़ से ज्यादा कंप्यूटिंग कार्य पूरे हो चुके हैं और इसके परिणामस्वरूप 1,500 से ज्यादा शोध पत्र प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। स्टार्टअप और एमएसएमई भी अपनी एचपीसी- आधारित परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए इन प्रणालियों का उपयोग कर रहे हैं।

तलाकशुदा बेटियों को पारिवारिक पेंशन

(जीएनएस)।

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 अधिसूचित किए हैं। इन नियमों और उसके बाद जारी दिनांक 26.10.2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ. सं.1/1(1)/2022-पी एंड पीडब्ल्यू(ई) में विभिन्न प्रावधान शामिल किए गए हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि इन नियमों के अंतर्गत आने वाले किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की तलाकशुदा/विधवा बेटी को उसकी बारी आने पर पारिवारिक पेंशन मिले। नीचे वर्णित समान प्रावधान रेलवे और रक्षा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अलग-अलग नियमों के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। इन नियमों के अनुसार:

किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के जीवित रहने पर उसके पति या पत्नी या बेटा या बेटी नहीं हैं जो पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है या वे उपर्युक्त नियमों में निर्धारित पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता की शर्तों को पूरा करना बंद कर देते हैं और पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई विकलांग बच्चा पात्र नहीं है, तो पारिवारिक पेंशन पच्चीस वर्ष की आयु के बाद आजीवन या उसके विवाह या पुनर्विवाह होने तक या उसके अपनी आजीविका कमाना शुरू करने तक, जो भी पहले हो, ऐसी स्थिति में पेंशन दी जाएगी या देय रहेगी, बशर्ते कि अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा बेटी अपने माता-पिता पर उस समय निर्भर थी जब वह जीवित थे। इसके अलावा, विधवा बेटी के मामले में, उसके पति की मृत्यु हो गई और तलाकशुदा बेटी के मामले में, उसका तलाक हुआ या सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या उसके पति या पत्नी के जीवनकाल के दौरान सक्षम न्यायालय में तलाक की कार्यवाही दायर की गई।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।